List

I. The Banks were allowed to appoint their own subbrokers to market the Bonds and pay brokerage to them at the approved rates and not on incremental basis, at the option of the broker.

II. The banks were not eligible for brokerage and/or collecting bank's commission for subscription mobilised by them from 16.12.1991. The brokerage payable to the sub brokers was required to be borne by the respective banks.

III. The rupee equivalent of the funds mobilised by them was required to be placed with them by SBI till the date of maturity of IDBs.

IV. Interest on the funds is payable by the banks to SBI every half year at the coupon rates of IDBs as also the principal amount.

V. A one time service fee of one per cent is payable unfront to SBI on the amount of funds placed with them to reimbures part of the expenses for publicity, printing etc. and for post issue servicing charges which will be borne by SBI.

Rupee Rouble Exchange Rate

III. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Wiil the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been disagreement between Jndia and Russia over Rupee Rouble exchange rate;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps have been taken by Government of India in this regard?

The MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESH WAR THAKUR): (a) to (c) Two rounds of inter-Governmental official level discussions have been held to discuss revision of the Rupee-Rouble exchange rate with is based on the November, 1978 protocol. The discussions have been inconclusive so far.

सकल घरेलू उत्पादन में गिरावट

112. **श्री रणजीत सिंह:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1992 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस में जी डी पी राइजिज बाई 5.6 परसेंट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सकल घरेलू उत्पादन की दर में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की वर्षवार दर कितनी-कितनी थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने यह आशंका व्यक्त की है कि सकल घरेलू उत्पादन की दर चालू वर्ष के दौरान 3 प्रतिशत तक गिर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1986-87 से लेकर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
1986-87	4.3
1987-88	4.2
1988-89	10.5
1989-90	6.0
1990-91	5.6

(घ) और (ङ) विभिन्न बृहत्-आर्थिक परिवर्तनों के अनन्तिम अनुमानों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में 1991-92 में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। पूर्वानुमानित निम्न सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि का कारण मुख्यतः वर्ष के पहले आठ महीनों (अप्रैल—नवम्बर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कमी होना और सामान्य मानसून की बजाय कम मानसून होना रहा जिससे पिछले वर्ष में प्राप्त किए गए स्तर की अपेक्षा 1991-92 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की संभावना है। लेकिन, अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधार-भूत ढांचे का अच्छा कार्य निष्पादन होने और सरकार द्वारा आरम्भ किए गए संरचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था में जल्दी ही सुधार होने और सतत उच्च वृद्धि पथ पर अग्रसर होने की संभावना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गयी धनराशि

113. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक पिछले कुछ वर्षों से भारी धनराशियों को बट्टे खाते में डालते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिये पिछले कुछ वर्षों के दौरान समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी किये थे;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित रीति तथा रिवाजों के अनुसार बैंक ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि प्रकट नहीं करते हैं जिनके लिए उनके सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक और बट्टे खाते डाली गई राशि के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस आवश्यकता के लिए बैंकों पर जोर देते रहे हैं कि वे ऋण मूल्यांकन और दिए गए अग्रिमों का कारगर पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करें। बैंकों से कहा गया है कि वे सख्त संयम अनुशासन तैयार करें ताकि अनियमित और खराब खातों का पहले पता लगया जा सके और अशोध्य ऋणों की घटनाओं को कम करने के लिए कारगर उपाय किए जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से कहा है कि वे अग्रिमों पर कारगर ढंग से निगरानी रखने और अनुवर्ती कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए किसी दिए गए समय पर अग्रिमों के स्वास्थ्य के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में उनके वर्गीकरण करने की प्रणाली स्थापित करें। बैंकों के निरीक्षण के समय भारतीय रिजर्व बैंक भी अग्रिमों की छानबीन करता है और जो अग्रिम अवरुद्ध होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं उपचारात्मक उपायों के लिए उन्हें बैंकों की जानकारी में लाया जाता है।

देश पर बकाया विदेशी कर्ज

114. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश पर विदेशी कर्ज की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के वर्ष के दौरान देश पर बकाया विदेशी कर्ज की मात्रा कितनी थी;

(ग) 1990-91 के वर्ष और 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार देश पर बकाया विदेशी कर्ज की राशि कितनी कितनी थी;

(घ) दिसम्बर, 1991 तक विदेशों से कुल कितना अतिरिक्त कर्ज लिया गया था और उस पर देय ब्याज की राशि कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो देश को विदेशी कर्ज से कब तक मुक्त करा लिए जाने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-81 के अंत में देश पर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि 18400 करोड़ रुपए थी।

(ग) वर्ष 1990-91 के अंत में देश पर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि 100425 करोड़ रुपए थी। 31 जनवरी, 1992 के अंत तक की सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि इस अवधि के खाते अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

(घ) दिसम्बर, 1991 तक प्राप्त किए गए अतिरिक्त ऋणों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस अवधि के खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) विदेशी उधार और उनकी वापसी अदायगी, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार, अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इन उधारों की योजना समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जिनमें पिछले ऋणों की वापसी अदायगी संबंधी अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। वर्तमान विदेशी ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि, 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित, 50 वर्ष है।

मुद्रास्फीति की दर

115. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1992 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "एन्युअल इन्फलेशन रेट हाइऐस्ट इन दी डिकेड" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;